



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2017/फाल्गुन 10, 1938

No. 75]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2017/PHALGUANA 10, 1938

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 13 फरवरी, 2017

सं. टीएमपी/57/2016-जेएनपीटी।—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में अंतरिम व्यवस्था के रूप में तदर्थ आधार पर स्टीवडोरिंग तथा तट प्रहस्तन परिचालनों के लिए अपक्रंत प्रशुल्क अनुमोदित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/57/2016-जेएनपीटी

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

आवेदक

कोरमः

- (i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री रजत सचर, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(फरवरी 2017 के 8वें दिन पारित)

यह मामला जेएनपीटी में स्टीवडोरिंग तथा तट प्रहस्तन परिचालनों के लिए अपक्रंत प्रशुल्क के निर्धारण हेतु जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने अपने पत्र सं. पीडी-11033/73/2013-पीटी (पीटी), दिनांक 14 जून, 2016 द्वारा महापत्तन न्यासों के लिए स्टीवडोरिंग तथा तट प्रहस्तन नीति, 2016 की प्रति अग्रेषित की है। तत्पश्चात, एमओएस ने, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अधीन, अपने पत्र सं. पीडी-11033/73/2013-पीटी (पीटी), दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 और 17 अक्टूबर, 2016 द्वारा महापत्तन न्यास

अधिनियम, 1963 की धारा 42(3) के अधीन महापत्तनों द्वारा प्राधिकृत स्टीवडोरिंग तथा तट प्रहस्तन परिचालनों के लिए अपक्रंत प्रशुल्क के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश जारी किए थे। एमओएस ने इस अति तत्काल मानने की सलाह देते हुए इस प्राधिकरण को नीति निर्देश रूप में दिशानिर्देश जारी किए हैं।

2.2. एमओएस द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुपालन में, इस प्राधिकरण ने 15 नवम्बर, 2016 को राजपत्र सं. 407 द्वारा स्टीवडोरिंग तथा तट प्रहस्तन परिचालनों के लिए अपक्रंत प्रशुल्क के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश अधिसूचित किए थे और 21 नवम्बर, 2016 को सभी महापत्तन न्यासों को सूचित किया था।

3. इस परिषेक्ष्य में, यद्यपि जेएनपीटी ने शुरू में अगस्त, 2016 में एक प्रस्ताव दाखिल किया था, इसने बाद में, परामर्श प्रक्रिया के आधार पर और हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण के आधार पर, दिसम्बर 2016 में संशोधित प्रस्ताव दाखिल किया था। इस प्रस्ताव पर भी परामर्श किया गया था। इस प्राधिकरण के अंतिम विचार के लिए मामला तैयार करने में कुछ और समय लगेगा।

4. इसलिए, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एमओएस ने इस प्राधिकरण को तत्काल कार्यवाई करने का निर्देश दिया है, इस प्राधिकरण ने पत्तन द्वारा स्टीवडोरिंग एवं तट प्रहस्तन परिचालनों और कार्यनिष्ठादन मानकों के लिए यथा प्रस्तावित अपक्रंत प्रशुल्क तर्दध आधार पर अंतरिम दर के रूप में अनुमोदित करने और परामर्श कार्यवाही के पूरा होने के बाद इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए जाने का निर्णय लिया है। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की जाने वाली अंतिम दरें भावी प्रभाव से लागू होंगी। तर्दध आधार रूप में अंगीकृत अंतरिम दर ऐसी ही मान्यता दी जाएगी। तर्दध दर और अंतिम दर के बीच भिन्नता की स्थिति में रिफ़ंड/वसूली, यदि कोई हो, का कोई प्रश्न नहीं होगा।

5.1. परिणमस्वरूप, और ऊपर स्पष्ट किए गए कारणों से, तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण **अनुबंध** रूप में संलग्न जेएनपीटी के लिए कार्यनिष्ठादन मानकों के साथ स्टीवडोरिंग तथा तट प्रहस्तन परिचालनों हेतु अपक्रंत प्रशुल्क अंतिम दरों के निर्धारण को लंबित रखते हुए पूरी तरह से तर्दध आधार पर अनुमोदित करता है। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की जाने वाली अंतिम दरें भावी प्रभाव से लागू होंगी।

5.2. स्टीवडोरिंग तथा तट प्रहस्तन दिशानिर्देशों के खंड 2.11 में कहा गया है कि स्टीवडोरिंग और अथवा तट प्रहस्तन परिचालन की शुरुआत से पहले, परिचालक दरमानों की अधिसूचना के लिए इस प्राधिकरण का रुख करेगा जिसमें महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 48 के अधीन यथा अपेक्षित स्टीवडोरिंग और अथवा तट प्रहस्तन प्रभार एवं कार्यनिष्ठादन मानक शामिल होने चाहिए। स्टीवडोरिंग तथा तट प्रहस्तन दिशानिर्देशों के खंड 2.3 के अनुसार, एक बार जब पत्तन के लिए विभिन्न घटकों के स्टीवडोरिंग तथा तट प्रहस्तन परिचालनों हेतु अपक्रंत प्रशुल्क सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं, तब यह सम्पूर्ण पत्तन पर एकसमान रूप से लागू होंगी जहां स्टीवडोरिंग तथा तट प्रहस्तन परिचालन निजी एजेंसियों अथवा प्रतिष्ठानों द्वारा किए जाते हैं।

5.3. इस संबंध में, यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 42 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सेवाओं के प्रावधान के लिए दरों के विनियमन के संदर्भ में, यह प्राधिकरण सभी महापत्तन न्यासों से पहले ही परामर्श कर निर्णय ले चुका है कि प्रशुल्क का विनियमन अलग-अलग सेवा प्रदाताओं के संदर्भ के बिना समग्र पत्तन के लिए किया जा सकता है। तदनुसार, इस प्राधिकरण ने निर्णय लिया था कि अधिकतम प्रशुल्क पत्तन विशेष के लिए निर्धारित किया जाएगा और संबद्ध पत्तन न्यास लाइसेंस जारी किए जाने के समय महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 42(3) के अनुसार प्राधिकृत किए जाने की शर्त तय करते हुए प्राधिकृत सेवा प्रदाता के लिए उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। इस प्राधिकरण का उक्त निर्णय पत्र सं. टीएमपी/47/2000-एमबीपीटी दिनांक 6 मई, 2002 द्वारा सभी महापत्तनों और पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) को संप्रेषित किया गया था। उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर और स्टीवडोरिंग तथा तट प्रहस्तन दिशानिर्देशों के खंड 2.3 के मद्देनजर, यह प्राधिकरण पत्तन को सलाह देता है कि लाइसेंस जारी किए जाने के समय इसे प्राधिकृत किए जाने की शर्त के रूप में बनाते हुए प्राधिकृत अलग-अलग स्टीवडोरिंग तथा तट प्रहस्तन परिचालक पर अधिकतम दरें लागू करें।

5.4. पत्तन से अनुरोध है कि कार्यनिष्ठादन मानकों के साथ स्टीवडोरिंग तथा तट प्रहस्तन परिचालनों हेतु तर्दध अपक्रंत प्रशुल्क लागू करने के लिए आवश्यक कार्यवाई करें।

टी. एस. वालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./444/16]

अनुबंध

जवाहरलाल नेहरू पत्तन च्यास
स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन सेवाओं के लिए तदर्थ अपक्रांत प्रशुल्क
भाग I – परिभाषाएँ और सामान्य शर्तें

(I). परिभाषाएँ:

- (i). “तटीय पोत” का अर्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस वाला भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी अन्य पत्तन अथवा स्थान के बीच व्यापार में विशेष रूप से लगाया गया पोत होगा।
- (ii). “विदेशगामी पोत” का अर्थ तटीय पोत से इतर कोई पोत होगा।
- (iii). “स्टीवडोरिंग” में पत्तन में पोतों पर किसी भी रूप में कार्गो की लदाई और उतराई तथा स्टोरेज शामिल है।
- (iv). ‘तट प्रहस्तन’ में हुक प्वाइंट को/से कार्गो व्यवस्थित करना और प्राप्त करना, घाट से स्टेक्यार्ड तक और विलोमतः अंतर मॉडल परिवहन और वैगनों/ट्रकों से/को कार्गो की प्राप्ति और डिलीवरी करना भी शामिल है।
- (v). ‘स्टीवडोर’ पत्तनों में पोतों पर किसी भी रूप में कार्गो की लदाई और उतराई तथा लंगरगाह के लिए एक अधिकृत एजेंट है और जिसे विनियमों के अधीन लाइसेंस दिया गया हो।
- (vi). ‘तट प्रहस्तन एजेंट’ हुक प्वाइंट को/से कार्गो व्यवस्थित करने और प्राप्त करने, घाट से स्टेक्यार्ड तक और विलोमतः अंतर मॉडल परिवहन और वैगनों/ट्रकों से/को कार्गो की प्राप्ति और डिलीवरी करने के लिए एक अधिकृत एजेंट है।

(II). सामान्य शर्तें:

- (i). पोत की हैसियत, जैसा सीमाशुल्क अथवा नौवहन महानिदेशक द्वारा इसका प्रमाणन किया गया हो, पोत संबंधित प्रभारों की वसूली के प्रयोजन के लिए ‘तटीय’ अथवा ‘विदेशगामी’ श्रेणी में वर्गीकरण के लिए निर्णयक कारक होगा; और, कार्गो की प्रकृति अथवा इसके मूल की इस प्रयोजन के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं होगी।
- (ii). **पोत संबंधित प्रभारों (वीआरसी) की वसूली के लिए पोत के वर्गीकरण की प्रणाली**

- (क). भारतीय धज वाला विदेशगामी पोत, जिसके पास सामान्य व्यापार लाइसेंस है, सीमाशुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय पोत में परिवर्तित हो सकता है। ऐसे पोत जो भारतीय पत्तन में उसकी प्रथम पत्तन आगमन पर सीमाशुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय चालन में परिवर्तित होता है, जब तक यह भारतीय तट पर नहीं पहुंचता है, किसी और सीमाशुल्क परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ख). विदेशी धज वाला विदेशगामी पोत महानिदेशक नौवहन द्वारा जारी तटीय यात्रा लाइसेंस के आधार पर तटीय पोत के रूप में परिवर्तन कर सकता है।

(iii). रियायती तटीय दर तथा विदेशी दर पर पोत संबंधित प्रभारों (वीआरसी) की वसूली हेतु मानदंड

- (क). ऐसे परिवर्तन के मामलों में लदान करने वाले पत्तन द्वारा पोत के तटीय सामग्रियों का लदान प्रारंभ करने के समय से तटीय दरें वसूल की जाएंगी।
- (ख). ऐसे परिवर्तन के मामले में तटीय दरें केवल तब तक प्रभार्य होंगी, जब तक पोत तटीय कार्गो का उतराई प्रचालन पूरा करता है, उसके तत्काल बाद विदेशगामी दरें उतराई पत्तन द्वारा वसूल की जाएंगी।
- (ग). महानिदेशक, नौवहन से प्राप्त तटीय लाइसेंस वाले नियत भारतीय तटीय पोतों के लिए तटीय दरों के हकदार होने के लिए अन्य दस्तावेज की अपेक्षा नहीं होगी।

(iv). रियायती तटीय दर पर कार्गो संबंधित प्रभारों (सीआरसी) की वसूली हेतु मानदंड

- (क). ‘विश्वव्यापी तथा तटीय’ परिचालन के लिए जारी किए गए सामान्य ट्रेइंग लाइसेंस वाले विदेशगामी भारतीय पोत प्रहस्तन प्रभारों (वीआरसी) के मामले में अर्थात् जलयान से तट स्थानांतरण और निम्नलिखित परिवृत्त्य में घाटशुल्क सहित घाट से/को भंडारण यार्ड और विलोमतः तटीय दरें लागू की जाएंगी:
 - (i). तटीय चालन में परिवर्तित और किसी भारतीय पत्तन से तटीय कार्गो की दुलाई करना और किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए गंतव्यित करना।

- (ii). तटीय चालन में * अपरिवर्तित परन्तु किसी भारतीय पत्तन से तटीय कार्गो की ढुलाई करना और किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए गतविधि करना।
 * कंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड का परिपत्र सं. 15/2002-सी, दिनांक 25 फरवरी, 2002 बिना किसी सीमाशुल्क परिवर्तन के भारतीय ध्वज वाले विदेशगामी पोतों में एक भारतीय पत्तन से भारत में दूसरे पत्तन तक तटीय कार्गो की ढुलाई की अनुमति देता है।
- (x). जहाजरानी महानिदेशक द्वारा जारी किए गए विनिर्दिष्ट अवधि अथवा नौप्रस्थान के लिए लाइसेंस और सीमाशुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय चालन में परिवर्तित विदेशी ध्वज वाले पोत के मामले में, किसी भारतीय पत्तन से लादा गया तथा किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए गतविधि तटीय कार्गो/कंटेनर तटीय कार्गो/कंटेनर के लिए लागू दर पर वसूल किया जाएगा।
- (v). सभी प्रभार भारतीय रूपयों में मूल्यवर्गित किए जाएंगे।
- (vi). यह प्रशुल्क बीओटी/बीओओटी परिचालकों अथवा निजी क्षेत्र भागीदारी के लिए किसी अन्य व्यवस्था हेतु लागू नहीं है जिन्हें 2005, 2008 और 2013 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों द्वारा शासित किया जाता है।
- (vii). यह प्रशुल्क एकसमान रूप से सम्पूर्ण पत्तन पर लागू होता है जहां निजी एजेंसियों अथवा फर्मों द्वारा स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालन किए जाते हैं।
- (viii). (क). अधिसूचित प्रशुल्क अधिकतम स्तर है।
 (ख). दरमान में निर्धारित दरों अधिकतम स्तर हैं; इसी तरह, रियायतें तथा छूट निम्नतम स्तर हैं। प्राधिकृत एजेंट, यदि वह ऐसा चाहे तो, निम्नतर दरों वसूल कर सकता है और/अथवा उच्चतर रियायतें अथवा छूट स्वीकृत कर सकता है।
 (ग). प्राधिकृत एजेंट भी, यदि वह ऐसा चाहे तो, दरमानों में निर्धारित दरों के कार्यान्वयन को शासित करने वाली निर्धारित दरों को युक्तिसंगत बना सकता है यदि ऐसा युक्तिकरण उपयोक्ताओं को दर प्रति इकाई में राहत देता है और दरमान में निर्धारित इकाई दरों अधिकतम स्तर से अधिक नहीं होंगी।
 (घ). तथापि, प्राधिकृत एजेंट को ऐसी निम्नतर दरों और/अथवा ऐसी दरों के कार्यान्वयन को शासित करने वाली शर्तों के युक्तिकरण के बारे में जनता को अधिसूचित करना होगा और ऐसी निम्नतर दरों और/अथवा ऐसी दरों के कार्यान्वयन को शासित करने वाली शर्तों में किन्हीं और बदलावों के बारे में जनता को अधिसूचित करते रहना होगा बर्तने निर्धारित की गई नई दरों टीएमपी द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक नहीं होंगी।
- (ix). प्राधिकृत एजेंट उसके द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं के लिए ही वसूली करेगा। लेबर के कल्पित आरक्षण और अन्य समान कल्पित प्रभारों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (x). यदि कोई नया कार्गो प्रहस्तित किया जाता है जो अधिसूचित नहीं किया गया हो/सूची में शामिल नहीं किया गया हो, तो पत्तन उस कार्गो के प्रहस्तन की प्रकृति, भौतिक विशेषताओं तथा पद्धति के आधार पर कार्गो श्रेणियों में से किसी एक के अधीन उस कार्गो को वर्गीकृत कर सकता है।
- (xi). जब पत्तन एमपीटी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार कार्गो की संरक्षा लेता है तो अन्य विविध गतिविधियों के लिए सेवाएं और विशिष्ट कार्गो के लिए प्रहस्तन प्रभार टीएमपी अधिसूचित दरमान के अनुसार पत्तन द्वारा वसूल किया जाता रहेगा।
- (xii). प्रशुल्क अधिकतम सीमाओं को मुद्रास्फीति से सूचकांकित किया जाता है परन्तु प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी और 31 दिसम्बर के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक ही। प्रशुल्क अधिकतम सीमा का ऐसा स्वतः समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और समायोजित प्रशुल्क अधिकतम सीमा प्रासंगिक वर्ष के 1 अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक लागू रहेगी।
- (xiii). (क). वाणिज्यिक परिचालन (सीओडी) की तरीख से उसी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक, प्रशुल्क उस वर्ष के लिए प्रासंगिक सूचकांकित अपक्रंत प्रशुल्क तक सीमित किया जाएगा, जोकि अधिकतम स्तर होगा। उर्ध्वकृत प्रशुल्क मानक प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2016 के पैरा 2.10 में यथा दिए गए सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष स्वतः ही संशोधित किया जाएगा जो सम्पूर्ण लाइसेंस अवधि के लिए लागू रहेगा।
 (ख). तथापि, परिचालक स्टीवडोरिंग तथा तट प्रहस्तन परिचालनों के लिए अपक्रंत प्रशुल्क के निर्धारण हेतु पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के खंड 7.1 में यथा विनिर्दिष्ट शुष्क बल्क कार्गो के लिए पत्र सं. पीडी-11033/73/2013-पीटी (पीटी), दिनांक 16 जून, 2016 द्वारा बर्थिंग नीति में यथा निर्धारित कार्यनिष्ठादान मानकों की उपलब्धि पर परिचालन के दूसरे वर्ष से 60 प्रतिशत डब्ल्यूपीआई सूचकांक की बजाय 100 प्रतिशत डब्ल्यूपीआई सूचकांकन के लिए हकदार है। ब्रेक बल्क कार्गो के लिए, इस दरमान के साथ यथा अधिसूचित कार्यनिष्ठादान मानक लागू होंगे।
 (ग). इस प्रयोजन के लिए, परिचालक स्टीवडोरिंग तथा तट प्रहस्तन परिचालनों के लिए प्रत्येक कार्गो हेतु अर्जित कार्गो वार औसत कार्यनिष्ठादान मानक के ब्योरों के साथ परिचालन के वित्तीय वर्ष के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर संबद्ध महापत्तन न्यास का रुख करेगा।
 (घ). महापत्तन न्यास कार्यनिष्ठादान मानकों की उपलब्धि का निर्धारण करेगा जो परिचालक द्वारा परामर्शदाता नियुक्त करते हुए अर्जित किया जाएगा यदि एक माह की अवधि में अपेक्षित हो।

- (ङ). परिचालक महापत्तन न्यास द्वारा परिचालक को इस लिखित पुष्टि पर 60 प्रतिशत की बजाय 100 प्रतिशत सूचकांकन लागू कर सकता है कि उसने अपफ्रंट प्रशुल्क के साथ अधिसूचित कार्यनिष्ठादान मानक अर्जित कर लिए हैं।
- (च). यदि महापत्तन न्यास पुष्टि करता है कि परिचालक ने पिछले 12 महीनों में टीएएमपी द्वारा यथा अधिसूचित कार्यनिष्ठादान मानक अर्जित नहीं किए हैं, परिचालक 100 प्रतिशत डब्ल्यूपीआई सूचकांकन के लिए हकदार नहीं होगा। परिचालक मानक प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2016 के खंड 2.9 में यथा निर्धारित 60 प्रतिशत सूचकांकन के साथ प्रशुल्क की वसूली जारी रखेगा।
- (xiv). सभी परिचालक पत्तन द्वारा लाइसेंसशुदा स्टीवडोरिंग/टट प्रहस्तन परिचालनों के मामले में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक महीने के भीतर कार्गो यातायात, जलयान बर्थ दिवस आउटपुट, प्रति पाली आउटपुट पर वार्षिक रिपोर्ट महापत्तन न्यास और टीएएमपी को भेजेंगे। टीएएमपी द्वारा अपेक्षा की जाने वाली कोई अन्य सूचना भी उन्हें समय-समय पर भेजी जाएगी।
- (xv). टीएएमपी परिचालकों तथा महापत्तन न्यासों से प्राप्त सभी ऐसी सूचना अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। तथापि, टीएएमपी प्रेषित किए गए ऐसे कुछ आंकड़ों/सूचना को प्रकाशित नहीं किए जाने के बारे में किसी परिचालक अथवा महापत्तन न्यास से प्राप्त अनुरोध पर विचार करेगा जो वाणिज्यिक तौर पर संवेदनशील हो सकते हैं। ऐसे अनुरोध-पत्रों के साथ प्रश्नाधीन आंकड़ों/सूचना की वाणिज्यिक संवेदनशीलता के बारे में विस्तृत औचित्य और प्रकाशित किए जाने पर उनके राजस्व/परिचालन पर आशंकित प्रतिकूल प्रभाव भी बताया जाएगा। इस संबंध में टीएएमपी का निर्णय अंतिम होगा।
- (xvi). विभिन्न घटकों के लिए निर्धारित कार्यनिष्ठादान मानदंड न्यूनतम होंगे जो परिचालक द्वारा अर्जित किए जाने चाहिए। ये कार्यनिष्ठादान मानदंड बोली दस्तावेज में शामिल किए जाएंगे।
- (xvii). परिचालक द्वारा वास्तव में अर्जित कार्यनिष्ठादान का अनुवीक्षण पत्तन और टीएएमपी दोनों द्वारा त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा। निर्धारित कार्यनिष्ठादान अर्जित करने में कोई कमी होने की स्थिति में, पत्तन परिचालक द्वारा पत्तन के साथ किए गए अनुबंध में दी गई शर्तों के अनुसार परिचालक पर कार्रवाई शुरू करेगा।
- (xviii). यदि किसी उपयोक्ता को टीएएमपी द्वारा यथा अधिसूचित कार्यनिष्ठादान मानकों के परिचालक द्वारा अनुपलब्धि के बारे में कोई शिकायत होती है तो वह टीएएमपी को अभ्यावेदन दे सकता है। उसके बाद, अभ्यावेदन पर जांच करवाई जाएगी और अपने निर्णय संबद्ध महापत्तन न्यास को दिए जाएंगे। महापत्तन न्यास अनुबंध की करार शर्तों के प्रावधानों के अनुसार निर्णयों पर जरूरी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।
- (xix). किसी अलग मद के सकल भार अथवा मात्रा द्वारा परिमाप अथवा क्षमता की गणना में, 0.50 तक दशमलवों को 0.50 इकाई रूप में लिया जाएगा और 0.50 और इससे अधिक के दशमलवों को एक इकाई के रूप में माना जाएगा, सिवाय जहां अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो।
- (xx). उपयोक्ताओं को परिचालक पर आरोप्य उपयुक्त स्तर से अधिक के विलंबों के लिए प्रभारों की अदायगी नहीं करनी होगी।
- (xxi). एमओएस द्वारा जारी किए गए और इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएएमपी/4/2004—सामान्य दिनांक 7 जनवरी 2005 तथा 15 मार्च, 2005 द्वारा अधिसूचित तटीय नीति निर्देश के अनुसार –
- (क). सभी तटीय कार्गो/कंटेनरों, ताप कोयला, पीओएल (कच्चा तेल सहित), लौह अयस्क और लौह अयस्क गुटिकाओं से इतर, के लिए कार्गो/कंटेनर संबंधित प्रभार सामान्य कार्गो/कंटेनर संबंधित प्रभारों के लिए तदनुरूपी प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (ख). कार्गो संबंधित प्रभारों के मामले में, घाटशुल्क सहित रियायती दरें जलयान तट स्थानांतरण और घाट से/को भंडारण यार्ड और विलोमतः के लिए सभी प्रासंगिक प्रहस्तन प्रभारों पर वसूल की जानी चाहिए।
- (ग). कंटेनर संबंधित प्रभारों के मामले में, रियायत समेकित बॉक्स दर पर लागू है। जहां मदवार प्रभारों की वसूली की जाती है, वहां जलयान तट स्थानांतरण और घाट से/को भंडारण यार्ड और विलोमतः के लिए सभी प्रासंगिक प्रभारों एवं कार्गो तथा कंटेनरों पर घाटशुल्क पर रियायत होगी।
- (जैसे और जब तटीय रियायत नीति पर एमओएस द्वारा जारी किए गए नीति निर्देश में परिवर्तन किया जाता है तो इसके बारे में पत्तन को संप्रेषित किया जाएगा।)
- (xxii). जिन स्टीवडोरिंग तथा तट प्रहस्तन एजेंसियों को जेएनपीटी द्वारा लाइसेंस जारी किया गया है वे ही जेएनपीटी में इन गतिविधियों का निष्पादन कर सकते हैं।
- (xxiii). सुरक्षित और कुशल स्टीवडोरिंग तथा तट प्रहस्तन परिचालन करने के लिए लाइसेंसशुदा स्टीवडोरिंग तथा तट प्रहस्तन एजेंसी को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं (जैसे मैनपावर, उपस्कर के गियर, शेकल्स, हुक्स, स्लिंग्स, हैवी लिफ्टिंग बीम्स, चेन स्लिंग्स, आदि) करनी होंगी।
- (xxiv). पोत पर कार्गो बांधना तथा खोलना पोत एजेंटी की जिम्मेदारी होगी। उपर्युक्त दरों में बांधना तथा खोलना प्रभार शामिल नहीं होंगे।
- (xxv). तट प्रहस्तन प्रभार केवल उस कार्गो के लिए लागू होते हैं जो कार्गो की लदाई/डिलीवरी से पहले जेएनपीटी परिसर में उतारा और भंडारित किया जाता है। ये परेषिती/पोतवणिक ट्रक पर सीधे लादे/उतारे गए कार्गो पर लागू नहीं हैं।
- (xxvi). पत्तन में/से कार्गो की प्राप्ति/डिलीवरी पोतवणिक/परेषिती अथवा उसके प्रतिनिधि की जिम्मेदारी मानी जाती है।

भाग - II

लाइसेंसशुदा स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन एजेंसियों द्वारा ब्रेक बल्क कार्गो के प्रहस्तन के लिए ऑन बोर्ड स्टीवडोरिंग तथा तट प्रहस्तन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अपक्रांत प्रशुल्क दें:

क्र. सं.	घटक समूह	प्रभार का आधार	उत्पादकता मानदंड	स्टीवडोरिंग प्रभार रु 0 में प्रति टन	तट प्रहस्तन प्रभार रु 0 में प्रति टन
1	बैग वाला कार्गो	प्रति टन	1200	103	207
2	जम्बो बैग	प्रति टन	1500	64	346
3	लौह और स्टील कोइलें और स्लैब	प्रति टन	4000	48	169
4	लौह और अयस्क – पाइप, ट्यूबें और प्लेटें	प्रति टन	1200	159	409
5	परियोजना कार्गो, मशीनरी और मशीनरी उत्पाद	प्रति टन	-	295	1195
6	आरओआरओ के माध्यम से इतर मोटर वाहन	प्रति इकाई	-	689	84

भाग - III**ब्रेक बल्क कार्गो के प्रहस्तन के लिए कार्यनिष्ठादान मानदंड**

क्र.सं.	घटक समूह	उत्पादकता मानदंड
1	बैग वाला कार्गो	1200
2	जम्बो बैग	1500
3	लौह और स्टील कोइलें और स्लैब	4000
4	लौह और अयस्क – पाइप, ट्यूबें और प्लेटें	1200
5	परियोजना कार्गो, मशीनरी और मशीनरी उत्पाद	-
6	आरओआरओ के माध्यम से इतर मोटर वाहन	-

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

Mumbai, the 13th February, 2017

No. TAMP/57/2016-JNPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves upfront tariff for Stevedoring and Shore Handling Operations on an adhoc basis at the Jawaharlal Nehru Port Trust, as an interim arrangement, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/57/2016-JNPT

Jawaharlal Nehru Port Trust

...
QUORUM

Applicant

- (i). Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 8th day of February, 2017)

This case relates to a proposal received from the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) for fixation of upfront tariff for Stevedoring and Shore Handling Operations at JNPT.

2.1. The Ministry of Shipping (MOS) vide its letter No.PD-11033/73/2013-PT (pt) dated 14 June, 2016 has forwarded a copy of Stevedoring and Shore Handling Policy for Major Ports, 2016. Subsequently, the MOS

vide its letter No.PD-11033/73/2013-PT (pt.) dated 7 October, 2016 and 17 October, 2016 has, under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963, issued the Guidelines for determination of Upfront Tariff for Stevedoring and Shore Handling Operations authorized by Major Ports under Section 42(3) of the Major Port Trusts Act, 1963. The MOS has issued the guidelines as policy direction to this Authority advising to treat it as most immediate.

2.2. In compliance with the direction issued by the MOS, this Authority has notified the Guidelines for Determination of Upfront Tariff for Stevedoring and Shore Handling Operations on 15 November, 2016 vide Gazette No.407 and intimated to all the Major Port Trusts on 21 November, 2016.

3. In this backdrop, though the JNPT had initially filed a proposal in August, 2016, it has subsequently, based on the information/ clarification sought by us and based on the consultation process, filed a revised proposal in December 2016. This proposal was also taken up on consultation. It will take some more time for this case to mature for final consideration of this Authority.

4. Therefore, and keeping in view that the MOS has directed this Authority for immediate action, this Authority decides to approve upfront tariff for stevedoring and shore handling operations and Performance Standards as proposed by the port as interim rate on an ad hoc basis pending final rates to be approved by this Authority. The final rates to be approved by this Authority will have prospective effect. The interim rate adopted in an ad hoc basis will be recognized as such. There will not be any question of refund/ recovery, if any, incase of variation between the adhoc rates and final rates.

5.1. In the result, and for the reasons explained above, and based on collective application of the mind, this Authority approves upfront tariff for Stevedoring and Shore Handling Operations alongwith the Performance Standards for the JNPT attached as **Annex**, purely on ad hoc basis pending fixation of final rates. The final rates to be approved by this Authority will have prospective effect.

5.2. Clause 2.11. of the Stevedoring and Shore Handling Guidelines states that before commencement of the stevedoring and or the shore handling operations, the operator will approach this Authority for notification of the Scale of Rates containing the ceiling rates of the stevedoring and or the shore handling charges and performance standards as required under Section 48 of the Major Port Trust Act, 1963. As per Clause 2.3 of the Stevedoring and Shore Handling Guidelines, once the upfront tariff caps are set out for stevedoring and shore handling operations of various commodities for a port, it will be applicable uniformly to the entire port where the stevedoring and shore handling operations are carried out by private agencies or firms.

5.3. In this regard, it is relevant to state that this Authority in consultation with all the Major Port Trusts had already, with reference to regulation of rates for provision of services by person authorised under Section 42 of the Major Port Trusts Act, 1963, decided that regulation of tariff can be done for the port as a whole without reference to individual service providers. Accordingly, this Authority had decided that ceiling tariff will be prescribed for a particular port and the port trust concerned will ensure their application to authorised service provider by making it a condition of authorisation in terms of Section 42(3) of the Major Port Trusts Act, 1963, while issuing the license. The said decision of this Authority was communicated to all the Major Ports and Ministry of Shipping (MOS) vide letter No. TAMP/47/2000-MBPT, dated 6 May, 2002. In view of the above position and keeping in view Clause 2.3. of the Stevedoring and Shore Handling Guidelines, this Authority advises the port to apply the ceiling rates to the authorised individual stevedoring and shore handling operator, by making it as a condition of authorization, while issuing licenses.

5.4. The port is requested to take necessary action for implementation of the adhoc upfront tariff for Stevedoring and Shore Handling operations along with Performance Standards.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./444/16]

Annex**JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST****AD HOC UPFRONT TARIFF FOR STEVEDORING AND SHORE HANDLING SERVICES****Part I - Definitions and General conditions****(I). Definitions:**

- (i). “Coastal vessel” shall mean any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal licence issued by the Directorate General of Shipping/ Competent Authority.
- (ii). “Foreign-going vessel” shall mean any vessel other than coastal vessel.
- (iii). ‘Stevedoring’ includes loading and unloading and stowage of cargo in any form on board the vessels in Port.
- (iv). ‘Shore handling’ includes arranging and receiving the cargo to/from the hook point, inter modal transport from wharf to stack yard and vice-versa and also receiving and delivering of cargo from/to wagons /trucks.
- (v). ‘Stevedore’ is an authorized agent for loading and unloading and anchorage of cargo in any form on board the vessels in ports and to whom the licence has been given under regulations.
- (vi). ‘Shore handling agent’ is an authorized agent for arranging the receiving the cargo to/ from the hook point, intermodal transport from wharf to stock yard and vice-versa and also receiving and delivering of cargo from/ to wagons/ trucks.

(II). General conditions:

- (i). The status of the vessel, as borne out by its certification by the Customs or the Director General of Shipping, shall be the deciding factor for classifying into ‘coastal’ or ‘foreign-going’ category for the purpose of levying vessel related charges; and, the nature of cargo or its origin will not be of any relevance for this purpose.
- (ii). System of classification of vessel for levy of Vessel Related Charges (VRC)
 - (a). A foreign going vessel of Indian flag having a General Trading Licence can convert to coastal run on the basis of a Customs Conversion Order. Such vessel that converts into coastal run based on the Customs Conversion Order at her first port of call in Indian Port, no further custom conversion is required, so long as it moves on the Indian Coast.
 - (b). A Foreign going vessel of foreign flag can convert to coastal run on the basis of a Licence for Specified Period or voyage issued by the Director General of Shipping and a custom conversion order.
- (iii). Criteria for levy of Vessel Related Charges (VRC) at Concessional Coastal rate and foreign rate
 - (a). In cases of such conversion, coastal rates shall be chargeable by the load port from the time the vessel starts loading coastal goods.
 - (b). In cases of such conversion coastal rates shall be chargeable till the vessel completes discharging operations at the last call of Indian Port; immediately thereafter, foreign going rates shall be chargeable by the discharge ports.
 - (c). For dedicated Indian coastal vessels having a Coastal licence from the Director General of Shipping, no other document will be required to be entitled to coastal rates.

- (iv). Criteria for levy of Cargo Related Charges (CRC) at Concessional Coastal rate
- (a). Foreign going Indian Vessel having General Trading License issued for ‘worldwide and coastal’ operation should be accorded applicable coastal rates with respect to Handling Charges (HC) i.e. ship to shore transfer and transfer from/to quay to/from storage yard including wharfage in the following scenario:
- (i). Converted to coastal run and carrying coastal cargo from any Indian Port and destined for any other Indian Port.
 - (ii). Not converted* to coastal run but carrying coastal cargo from any Indian Port and destined for any other Indian Port.
- * The Central Board of Excise and Customs Circular No.15/2002-Cus. Dated 25 February, 2002 allows carriage of coastal cargo from one Indian port to another port in India, in Indian flag foreign going vessels without any custom conversion.*
- (b). In case of a Foreign flag vessel converted to coastal run on the basis of a Licence for Specified Period or voyage issued by the Director General of Shipping, and a Custom Conversion Order, the coastal cargo/container loaded from any Indian Port and destined for any other Indian Port should be levied at the rate applicable for coastal cargo/container.
- (v). All the charges shall be denominated in Indian Rupees.
- (vi). This tariff is not applicable for BOT/BOOT operators or any other arrangement for private sector participation who are governed by the Tariff Guidelines of 2005, 2008 and 2013.
- (vii). This tariff is applicable uniformly to the entire port where the stevedoring and shore handling operations are carried out by private agencies or firms.
- (viii). (a). The tariff notified is ceiling level.
- (b). The rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels; likewise, rebates and discounts are floor levels. The authorized agent may, if he so desires, charge lower rates and/or allow higher rebates and discounts.
- (c). The authorized agent may also, if he so desire, rationalise the prescribed conditionalities governing the application of rates prescribed in the Scale of Rates if such rationalisation gives relief to the users in rate per unit and the unit rates prescribed in the Scale of Rates do not exceed the ceiling level.
- (d). The authorized agent should, however, notify the public such lower rates and/ or rationalisation of the conditionalities governing the application of such rates and continue to notify the public any further changes in such lower rates and/or in the conditionalities governing the application of such rates provided the new rates fixed shall not exceed the rates notified by the TAMP.
- (ix). The authorized agent shall charge only for services provided by him. No notional booking of labour and other similar notional charges would be permitted.
- (x). If any new cargo is to be handled which is not notified/not included in the list, then the port may categorise that cargo under any one of the cargo categories based on the nature, physical characteristics and the method of handling that cargo.
- (xi). Services for other miscellaneous activities and also the handling charges for specific cargoes when Port takes custody of cargo as per Section 42 of MPT Act shall continue to be levied by Port as per TAMP notified SOR.

- (xii). Tariff caps are indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in the Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1st January and 31st December of the relevant year. Such automatic adjustment of the tariff cap will be made every year and the adjusted tariff cap will come into effect from 1st April of the relevant year till 31st March of the following year.
- (xiii). (a). From the date of Commercial Operation (CoD) till 31st March of the same financial year, the tariff would be limited to the indexed upfront tariff relevant to that year, which would be the ceiling. The aforesaid tariff shall be automatically revised every year based on an indexation as provided in para 2.10. of the normative tariff guidelines, 2016 which will be applicable for the entire License period.
- (b). The operator, however, is entitled to 100% WPI indexation instead of 60% WPI indexation, from the second year of operation on achievement of performance standards as prescribed in the Berthing Policy vide letter No.PD-11033/73/2013-PT(pt.), dated 16 June, 2016 for dry bulk cargo as stipulated in clause 7.1. of the guidelines issued by the Ministry of Shipping for fixation of upfront tariff for stevedoring and shore handling operations. For break bulk cargo, the Performance Standards as notified along with this Scale of Rates will be applicable.
- (c). For this purpose, the Operator shall approach the concerned Major Port Trust within 30 days of completion of financial year of operation along with details of cargo wise average Performance standard achieved for each cargo for both stevedoring and shore handling operations.
- (d). The Major Port Trust shall ascertain the achievement of performance standards claimed to have been achieved by the operator by engaging Consultant if required in one month's time.
- (e). The operator can apply 100% indexation instead of 60% on written confirmation by the Major Port Trust to the operator that it has achieved the Performance Standards notified along with the upfront tariff.
- (f). In the event the Major Port Trust confirms that the operator has not achieved the Performance Standards as notified by TAMP in previous 12 months, the operator will not be entitled for 100% WPI indexation. The operator will continue to levy the tariff with 60% indexation as prescribed at clause 2.9. of the normative tariff guidelines, 2016.
- (xiv). All the operators shall furnish to the Major Port Trust and TAMP annual reports on cargo traffic, ship berth day output, per shift output within a month following the end of financial year in respect of stevedoring/ shore handling operations licensed by the port. Any other information which may be required by TAMP shall also be furnished to them from time to time.
- (xv). TAMP shall publish on its website all such information received from operators and Major Port Trusts. However, TAMP shall consider a request from any operator or Major Port Trust about not publishing certain data/ information furnished which may be commercially sensitive. Such requests should be accompanied by detailed justification regarding the commercial sensitiveness of the data/ information in question and the likely adverse impact on their revenue/ operation of upon publication. TAMP's decision in this regard would be final.
- (xvi). The performance norms prescribed for various commodities shall be the minimum that should be achieved by the operator. These performance norms shall be incorporated in the bid documents.
- (xvii). The performance actually achieved by the operator shall be monitored by both the Port and the TAMP on a quarterly basis. In the event of any shortfall in achieving the performance prescribed, the Port will initiate action on the operator as per the terms contained in the agreement entered into with the operator by the Port.

- (xviii). In the event any user has any grievance regarding non-achievement by the operator of the Performance Standards as notified by the TAMP, he may prefer a representation to TAMP which, thereafter, shall conduct an inquiry into the representation and give its finding to the concerned Major Port Trust. The Major Port Trust will be bound to take necessary action on the findings as per the provisions of the contract conditions of the Agreement.
- (xix). In calculating the gross weight or measurement by volume or capacity of any individual item, fractions upto 0.50 shall be taken as 0.50 unit and fractions of 0.50 and above shall be treated as one unit, except where otherwise specified.
- (xx). Users will not be required to pay charges for delays beyond reasonable level attributable to the operator.
- (xxi). As per coastal policy direction issued by the MOS and notified by this Authority vide Order No.TAMP/4/2004-Genl., dated 7 January, 2005 and 15 March, 2005 -
 - (a). The cargo/container related charges for all coastal cargo/containers, other than thermal coal, POL (including crude oil), iron ore and iron ore pellets, should not exceed 60% of the corresponding charges for normal cargo/container related charges.
 - (b). In case of cargo related charges, the concessional rates should be levied on all the relevant handling charges for ship shore transfer and transfer from/to quay to/from storage yard including wharfage.
 - (c). In case of container related charges, the concession is applicable on composite box rate. Where itemised charges are levied, the concession will be on all the relevant charges for ship shore transfer and transfer from/to quay to/from storage yard as well as wharfage on cargo and containers.

(As and when there is a change in the policy direction issued by the MOS on the coastal concession policy, the same will be communicated to the port.)

- (xxii). Stevedoring & Shore Handling Agencies who have been issued license by JNPT can only undertake to perform these activities at JNPT.
- (xxiii). The licensed Stevedoring & Shore Handling Agency has to make all necessary arrangements (such as manpower, bringing equipment's, gears, shackles, hooks, slings, heavy lifting beams, chain slings, etc.) for carrying out safe and efficient Stevedoring & Shore Handling operations.
- (xxiv). Lashing and Unlashing of cargo on board the vessel shall be the responsibility of vessel agent. The above rates do not include lashing and unlashing charges.
- (xxv). Shore handling charges are applicable only for the cargo which is off loaded and stored in JNPT premises before loading/delivery of cargo. These are not applicable to cargo directly loaded from/discharged on consignee/shipper truck.
- (xxvi). The receipt/delivery of cargo in/from JNPT is considered the responsibility of shipper/consignee or their representative.

Part - II

Upfront Tariff rates for Providing On board Stevedoring and Shore Handling Services for handling of Break Bulk cargo's by the Licensed Stevedoring and Shore Handling agencies:

Sr. No.	Commodity Group	Basis of Charge	Productivity Norm	Stevedoring Charges in ` per tonne	Shore Handling Charges in ` per tonne
1	Bagged cargo	Per Ton	1200	103	207
2	Jumbo bags	Per Ton	1500	64	346
3	Iron & steel-coils and slabs	Per Ton	4000	48	169
4	Iron & steel – pipes, tubes, plates	Per Ton	1200	159	409
5	Project cargo, Machinery and machinery products	Per Ton	-	295	1195
6	Motor vehicles other than through RORO	Per unit	-	689	84

PART – III**Performance Norms for handling of Break Bulk cargo**

Sr. No	Commodity Group	Productivity Norm
1	Bagged cargo	1200
2	Jumbo bags	1500
3	Iron & steel-coils and slabs	4000
4	Iron & steel – pipes, tubes, plates	1200
5	Project cargo, Machinery and machinery products	-
6	Motor vehicles other than through RORO	-